

सजग भाषा

◀ 1-15 सितंबर, 2024 ◀ वर्ष: 2 ◀ अंक: 11

निःशुल्क प्रति



आने वाला समय भारत की **भाषाओं** का



हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी बने, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है

किसी भी भारतीय भाषा के साथ स्पर्धा के बिना हमें हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाना है



अनुक्रमणिका

हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी बने, इस लक्ष्य के साथ...	10
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को मिला...	12
राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर स्मारक टिकट जारी	13
रेल संपर्क के विस्तार से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति	18
35 वर्षों से चल रहा संघर्ष हुआ समाप्त	19
साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत स्तंभ बना 'I4C'	20
राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों के समग्र समाधान...	22
नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए उन्नत तकनीक...	23
पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता का नाम है 'एसवीपीएनपीए'	24
सरोकार, सरकार और समाज	25
विशेष लेख	26

विशेष रिपोर्ट



05 आने वाला समय भारत की भाषाओं का

14 भारत सेमीकंडक्टर्स के लिए वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है: श्री नरेन्द्र मोदी

16 नए भारत की नई कूटनीति दिखी सिंगापुर और ब्रुनेई में

संपादक की कलम से...

हिंदी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कामकाज में इसे प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हिंदी, जो कि भारत की राजभाषा है, अब न केवल सरकारी दस्तावेजों में बल्कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में भी प्रमुखता से उपयोग की जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजभाषा हिंदी ने देश ही नहीं, वैश्विक मंचों पर भी पहले से अधिक सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशानुसार अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा आयोजित बैठकों, संवाददाता सम्मेलनों और सरकारी घोषणाओं में हिंदी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यह कदम न केवल हिंदीभाषी जनता को सीधे जानकारी पहुंचाने में सहायक है, बल्कि सरकारी नीतियों एवं योजनाओं को व्यापक रूप से समझाने और लागू करने में भी मदद करता है।

विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने के लिए हिंदी में सामग्री तैयार की जा रही है। देश में तीन नए कानून बने, एक जुलाई, 2024 से पूरे देश में लागू हुए तो इसकी सामग्री अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में बनाई गई और उसे प्रसारित किया गया है। इस काम में केंद्रीय गृह मंत्रालय के

निर्देश पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने महती भूमिका निभाई है।

ऐसे बहुत से अन्य कई काम हुए हैं और हो रहे हैं जिनसे न केवल हिंदी भाषा की मान्यता बढ़ी है, बल्कि आम जनता के बीच सरकारी कामकाज के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी, और अन्य क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों और सरकारी निकायों द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान हिंदी को एक कार्यात्मक और संवादात्मक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं।

इस बढ़ती उपयोगिता से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी न केवल भारतीय संस्कृति की पहचान है, बल्कि यह एक प्रभावी और आवश्यक भाषा भी बनती जा रही है, जिससे सरकारी कामकाज और नीति निर्माण में सुधार संभव हो सके।

'सजग भारत' का यह अंक इसी विषय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमें बेहद खुशी है कि कई माध्यमों से आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक आ रही हैं। इस

संबंध को बनाएं रखें। हमारा ईमेल है sajag-bharat@bprd.nic.in

जय हिंद!

राजीव कुमार शर्मा

महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

“**प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी राजभाषा हिंदी ने देश ही नहीं, वैश्विक मंचों पर भी पहले से अधिक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया है।**”



श्री विजयपुरम का नाम अंडमान और निकोबार द्वीपों के गौरवशाली इतिहास और वीर व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह नाम हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें हम औपनिवेशिक सोच से मुक्त होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान और उत्सव मनाने का संकल्प लेते हैं।



श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



साइबर सुरक्षा केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित होकर नहीं रह गयी, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अहम पहलू बन गयी है।



श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक के मुफ्त उपचार का लाभ मिलेगा।



श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री



पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखना हमारी गौरवशाली विरासत को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, जहां नेताजी के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था और सेल्युलर जेल में दिए गए बलिदानों ने आजादी की गाथा लिखी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय स्थान रखते हैं। यह नाम परिवर्तन हमारे देश की शक्ति और उन सच्चे नायकों व उनकी विरासत को सम्मान देने की दृष्टि को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री



श्री @narendramodi जी और श्री @AmitShah जी का हृदय से आभार, जिन्होंने अतीत को स्मरण कर हमारे भविष्य को पुनर्प्राप्त करने का साहसिक कदम उठाया है।

श्री बंडी संजय कुमार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2024 का उद्घाटन किया।



गृह मंत्रालय
भारत सरकार

आने वाला समय भारत की भाषाओं का



भारत, विविधताओं से परिपूर्ण एक अद्वितीय देश, अपनी भाषाओं और संस्कृतियों की समृद्धि के लिए जाना जाता है। बीते दशक में जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं को लेकर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का अनुराग है, वह वैश्विक मंच पर भी राजभाषा हिंदी के लिए सुखद है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह लगातार राजभाषा हिंदी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग पहले से अधिक किया जाने लगा है। आने वाला समय इन भाषाओं के उत्थान और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

ब्यूरो

भा

रत की भाषाएं न केवल हमारी पहचान हैं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी प्रतीक हैं। राजभाषा हिंदी हीरक जयंती मना रही है। 75 वर्षों की

गौरवपूर्ण यात्रा को और अधिक जनहितैषी बनाया जा रहा है। समय के साथ उसे आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कई मंचों पर मातृभाषा को लेकर अपना प्रेम जगजाहिर किया है। वे कहते हैं कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। 14 सितंबर, 2024 को जब



संविधान सभा की एक स्पिरिट थी कि एक स्वदेशी भाषा में देश के सभी नागरिक एक-दूसरे के साथ संवाद करें, चाहे वह हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या गुजराती हो। हिंदी को मजबूत करने से इन सभी भाषाओं में एक प्रकार से लचीलापन भी आएगा, समृद्धि भी आएगी।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने भारत मंडपम में अपना संबोधन दिया, तो अतीत के गर्व के साथ ही भविष्य के संकल्प को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदी की 75 वर्षों की यह यात्रा अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के अंतिम पड़ाव पर खड़ी है और आज का दिन हिंदी को संपर्क, जन भाषा, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने का दिन है। इस अवसर पर श्री शाह ने राजभाषा हीरक जयंती के उपलक्ष्य में विशेष रूप से तैयार की गई 'राजभाषा भारती' पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण किया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने राजभाषा गौरव तथा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति योगदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में श्री अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ भी किया, जो भारतीय भाषाओं के विकास और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भाषाई समृद्धि के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करेगा, बल्कि सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देगा। श्री अमित शाह ने सभी से आग्रह किया कि

वे अपनी मातृभाषा का उपयोग करें और इसे आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति, और संस्कृति के प्रति समर्पित लोग उपस्थित थे, जिन्होंने राजभाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भाषाई समृद्धि का महत्व

भारतीय भाषाओं का संरक्षण और विकास न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक एकता, शिक्षा और विकास में भी योगदान करता है। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने से लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी एक प्रकार से सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और एक-दूसरे की पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बांग्ला हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है। इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी हों, महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभभाई पटेल हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस

हों या फिर आचार्य कृपलानी हों, हिंदी को बढ़ावा देने वालों में अधिकतर गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में जो समिति बनाई गई, वह समिति भी श्री आर्यंगर और श्री के. एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने की एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखी थी। दोनों नेता गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे।

शिक्षा में भाषा की भूमिका

शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा में शिक्षा लेने से छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। सरकार की योजनाओं और पहलों के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हम आज शिवाजी महाराज के स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के सिद्धांत पर बल देकर काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने का काम किया है। बच्चे की अभिव्यक्ति, सोचने, समझने, तर्क, विश्लेषण और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया की सबसे सुगम भाषा उसकी मातृभाषा होती है। इसी कारण से प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने मातृभाषा में शिक्षा पर बहुत बल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत की सभी भाषाओं को मजबूत करने और राजभाषा को देश की संपर्क भाषा बनाने का दिन है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं में अपने देश का कामकाज कर सकें।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि आज भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ हुआ है और हम सब इस छोटे से बीज के बोए जाने के साक्षी बने हैं। वह आने वाले वर्षों में एक वटवृक्ष बन कर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केन्द्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि

राजभाषा का प्रचार-प्रसार तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इनके साथ संवाद स्थापित न करें।

डिजिटल युग और भाषाई विविधता

डिजिटल माध्यमों का उदय भारत की भाषाओं के लिए एक नया मंच प्रदान करता है। ऑनलाइन सामग्री और मोबाइल ऐप्स के जरिए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे युवा पीढ़ी अपनी भाषाओं में संवाद करने के लिए प्रेरित होगी। श्री अमित शाह का कहना है कि हमने इन 10 वर्षों के अंदर 'कंठस्थ' टूल बनाया। हमने इन 10 वर्षों के अंदर संसदीय राजभाषा समिति के चार प्रतिवेदन जमा किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण, उनका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को बहुत मजबूती मिलेगी।

भाषा और तकनीकी विकास

आने वाले समय में भाषाई तकनीक, जैसे कि अनुवाद ऐप्स और वॉयस असिस्टेंट, भारतीय भाषाओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेंगे। यह भाषाओं को तकनीकी दुनिया में भी एकीकृत करेगा और विभिन्न भाषाओं के बीच की खाई को कम करेगा। श्री शाह ने कहा कि कई शब्द हिंदी में नहीं हैं, लेकिन अन्य स्थानीय भाषाओं में हैं और हमने उन्हें स्वीकार किया है। हिंदी जब इन शब्दों को स्वीकार करती है, तो हमारी स्थानीय भाषाएं भी हिंदी के कई शब्दों को स्वीकारती हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमने हिंदी शब्द सिंधु शब्द कोष में भारत की हर



नई दिल्ली के भारत मंडपम में राजभाषा हीरक जयंती समारोह एवं चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल हुए।

भाषा के शब्दों को समाहित किया है। हमें हिंदी को स्वीकार्य, लचीली और बोलचाल की भाषा बनाना चाहिए। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 5 वर्षों में हिंदी शब्द सिंधु शब्द कोष विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश बनेगा।

अभिभावकों से की गई अपील

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी भाषाओं को अगर कोई बचा सकता है, तो वो केवल माताएं ही बचा सकती हैं। गृह मंत्री ने सभी अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही बात करें। उन्होंने कहा कि अगर हम ये करते हैं तो हमारी भाषाओं को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हमारी भाषाएं चिरकाल तक देश और दुनिया की सेवा करती रहेंगी। अब इस देश को कोई भी किसी भी प्रकार की गुलामी में नहीं रख सकता और भाषा की गुलामी में तो कभी नहीं रख सकता।

संस्कृति और कलात्मकता

भारतीय भाषाएं कला, साहित्य और संगीत के माध्यम से भी समृद्ध

स्वभाषा, स्वभूषा और स्वसंस्कृति के आंदोलनों से विकसित हुई हिंदी भाषा और भारतीय भाषाओं में आपसी सामंजस्य से ही हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

हैं। आने वाले समय में स्थानीय भाषाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के प्रयासों से संस्कृति को नया आयाम मिलेगा। यकीनन आने वाला समय भारत की भाषाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि हम अपनी भाषाओं का संरक्षण और विकास करते हैं, तो यह न केवल

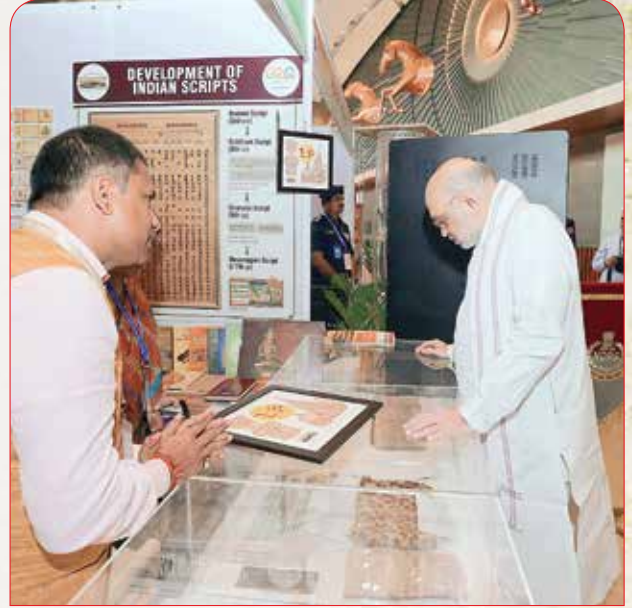
हमारी पहचान को सुरक्षित रखेगा, बल्कि देश की एकता और सामाजिक समरसता को भी मजबूत करेगा। भाषाएं हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उनका सम्मान और विकास करना हमारी जिम्मेदारी है।

संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन चुकी है हिंदी

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विश्व के बड़े से बड़े मंच पर विश्वास और गौरव के साथ हिंदी में अपना संबोधन देकर हिंदी की स्वीकृति को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन चुकी है और यह 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा भी बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि 10 जून, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित बहुभाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ।

भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार-प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और इसके प्रयोग में वृद्धि के लिए निरंतर उपाय कर रही है। हिंदी पहले से ही यूनेस्को की नौ कामकाजी भाषाओं में से एक है। वर्ष 2014, 2019, 2020 और 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में प्रधानमंत्री के संबोधन सहित भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में वक्तव्य दिए हैं।

वर्ष 2018 में, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच दो साल की अवधि के लिए एक स्वैच्छिक वित्तीय योगदान संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2019 में इस करार की अवधि को 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया था और वर्तमान में यह मार्च 2025 तक लागू है। इस करार के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र समाचार की एक हिंदी वेबसाइट पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को यूएन रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में प्रसारित करता है, साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है, यूएन ब्लॉग को हिंदी में प्रकाशित करता है और एंड्रॉइड एवं आईओएस मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए यूएन न्यूज रीडर मोबाइल एप्लिकेशन को हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। हिंदी का बढ़ता हुआ महत्व न केवल भारत के लिए, बल्कि विश्व के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि हिंदी भाषा अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रही है। ■



राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन करते केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह।

हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं पर भी जोर

गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता भारत की भाषाई विविधता और एकता का प्रमाण है। यह देश के विकास और एकता को मजबूत करने में एक सशक्त माध्यम बन रही है। हिंदी का प्रसार और स्वीकार्यता केवल भाषा की जीत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय की दिशा में बढ़ते कदम का संकेत है। 12 और 13 सितंबर 2024 को, राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान और लुप्तप्राय भाषा केंद्र, विश्वभारती ने 'प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनजातीय भाषाओं और भारतीय बहुभाषावाद के संरक्षण: नीति और व्यवहार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी' का आयोजन किया। यह संगोष्ठी भारतीय जनजातीय भाषाओं और बहुभाषावाद के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित थी।

हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी बने, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है

किसी भी भारतीय भाषा के साथ स्पर्धा के बिना हमें हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाना है



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह को फिर से सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा है कि उनका मंत्रालय वर्ष 2047 तक देश की सभी सरकारी व्यवस्थाओं का संचालन भारतीय भाषाओं में करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस दृष्टिकोण पर जोर दिया कि देश की विविधता को देखते हुए, विभिन्न भाषाओं को समान सम्मान दिया जाना चाहिए।

ब्यूरो

कें द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव उनकी निरंतरता और राजभाषा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के विकास और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है, ताकि भारत की भाषाई विविधता को सम्मानित किया जा सके। श्री शाह की अध्यक्षता में समिति पहले ही कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है, जिनसे देश में भाषाई समावेशिता को बढ़ावा मिला है। उनकी अध्यक्षता में समिति आगे भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए नई योजनाएं और पहलों पर कार्य करेगी।

नई सरकार के गठन के बाद 9 सितंबर को संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को समिति का अध्यक्ष चुना गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 से वर्ष मई, 2024 के दौरान भी श्री अमित शाह समिति के अध्यक्ष थे। संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के उपबंधों के अंतर्गत वर्ष 1976 में किया गया था। समिति में 30 संसद सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोक सभा और 10 राज्य सभा सदस्य होते हैं। बैठक में संसदीय राजभाषा समिति के लिए मनोनीत किए गए राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ राजभाषा विभाग की सचिव, श्रीमती अंशुली आर्या के नेतृत्व में राजभाषा विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। संसदीय समिति के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 75 वर्षों से हम राजभाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विगत 10 वर्षों में इसके तरीके में



संसदीय राजभाषा समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह।

थोड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि के एम मुंशी और एन जी आर्यंगर ने बहुत सारे लोगों से विचार-विमर्श करके ये तय किया था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने और इसे सरकारी कामकाज में आगे बढ़ाने के क्रम में किसी भी स्थानीय भाषा के साथ हिंदी की स्पर्धा न हो। जब बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होती है, तो वह अन्य भारतीय भाषाएं भी आसानी से सीख लेता है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा है कि सहकार और स्वीकृति हमारे कार्य का मूल आधार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ना है, जिससे वर्ष 2047 में स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश का संपूर्ण संचालन भारत की भाषाओं में किया जा सके।

उनके इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि वे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत भाषा आधार तैयार किया जा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में संसदीय राजभाषा समिति ने यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की 'सहेली' बने। यह स्पष्ट किया कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थानीय भाषा के बोलने वालों के मन में हीनभावना न आए। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदी को सामान्य रूप से एक कार्य भाषा के रूप में सर्वसम्मति और सहमति से स्वीकार किया जाना चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी अब एक प्रकार से रोजगार एवं तकनीक के साथ जुड़ गई है और नए युग की सभी तकनीकों को हिंदी भाषा से युक्त करने के लिए भारत सरकार भी विशेष प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति में सभी मातृभाषाओं को महत्व देने का संकल्प लिया गया है उसे ये समिति बहुत आगे बढ़ाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा विभाग इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बना रही है, जिससे आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं का अपने आप



हमें 1000 साल पुरानी हिंदी भाषा को एक लंबे समय तक नया आयुष्म देना है और इसे स्वीकृत बनाना है। हमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हमें छोड़े गए कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

तकनीकी आधार पर अनुवाद हो जाए। इस कार्य के पूरा हो जाने पर हमारे कामकाज में हिंदी की बहुत तेज गति से स्वीकृति और विकास होगा। विगत 5 वर्षों में हमने बहुत परिश्रम कर समिति के प्रतिवेदन के तीन बड़े खंड राष्ट्रपति को दिए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमें इस गति को बरकरार रखना है। ■

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को मिला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार



यह पुरस्कार उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने हिंदी को सरकारी कामकाज में लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। यह पुरस्कार न केवल विभाग के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

ब्यूरो



ह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से वर्ष 2023-2024 के लिए, 300 से कम कर्मियों वाले मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में राजभाषा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित समारोह एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत सचिव श्री वी. श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया।

इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने हिंदी को सरकारी कामकाज में लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने विभाग की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुरस्कार न केवल विभाग के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है। विभाग ने अपने प्रयासों के चलते राजभाषा का उपयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह विभाग अपने अनुभागों और इससे जुड़े कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में संघ की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करता है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में सचिव की अध्यक्षता में

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से संबंधित कार्यालय के प्रमुख एवं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं। विभाग में प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।

बैठक में विभाग एवं उससे जुड़े कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के संबंध में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत समीक्षा की गई और हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरीकों पर विचार किया गया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिंदी में किए गए कार्यों का आकलन करने हेतु, विभिन्न अनुभागों से जानकारी जुटाकर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है और नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसके साथ ही, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की स्थापना हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह पुरस्कार उन संस्थानों और विभागों को दिया जाता है, जो हिंदी के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान देते हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डीएआरपीजी, डीओपीटी और डीओपी एंड पीडब्ल्यूडी की एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति है। इसकी बैठक माननीय कार्मिक राज्य मंत्री की अध्यक्षता में समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं। ■

राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर स्मारक टिकट जारी

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राजभाषा के हीरक जयंती कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक डाक टिकट जारी किया। इस कार्यक्रम से देश के प्रशासनिक ढांचे में हिंदी की महत्ता को सभी के सामने लाया गया।

ब्यूरो

14

सितंबर, 2024 का दिन भारत के भाषायी इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन देश ने राजभाषा हिंदी की हीरक जयंती मनायी है। यह ऐतिहासिक दिन हमें

संविधान सभा के उस निर्णय की याद दिलाता है, जो 14 सितंबर, 1949 को लिया गया था, जब हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।

राजभाषा विभाग ने वर्ष 2024-25 को राजभाषा हीरक जयंती वर्ष घोषित किया है। इस महत्वपूर्ण वर्ष में भारतीय डाक विभाग की ओर से एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। स्मारक डाक टिकट

से बीते 75 वर्षों में देश के प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में हिंदी की यात्रा तथा इसके स्थायी महत्व को रेखांकित किया गया है। पांच रुपये मूल्य के इस स्मारक डाक टिकट को भारत की एकता को प्रोत्साहित करने और विविध भाषायी समुदायों की सेवा करने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने डाक टिकट जारी करते हुए हिंदी की सांस्कृतिक और प्रशासनिक भूमिका को दोहराया, जो पिछले 75 वर्षों से देश के शासन में केंद्रीय भूमिका निभा रही है।

भारत की राजभाषा पर बहस 12

सितंबर, 1949 को शुरू हुई और 14 सितंबर, 1949 को समाप्त हुई, जब संविधान सभा ने व्यापक चर्चाओं के बाद हिंदी को राज्य की भाषा के रूप में चुना। इस निर्णय को बाद में वर्ष 1963 के राजभाषा अधिनियम द्वारा सुदृढ़ किया गया, ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। इसके बाद, वर्ष 1968 का राजभाषा प्रस्ताव और 1976 के आधिकारिक भाषा नियमों ने केंद्र सरकार के मामलों में हिंदी को और संस्थागत बनाया।

वर्ष 1975 में अपनी स्थापना के बाद से, राजभाषा विभाग, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ने विभिन्न केंद्र सरकार के मंचों पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभाग के प्रयासों का केंद्र संविधान में हिंदी से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और आधिकारिक मामलों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

‘भारतीय भाषा अनुभाग’ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधिकारिक पत्राचार को उनकी संबंधित भाषाओं में सुगम बनाता है। विभाग ने हिंदी को हिंदी दिवस और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। जिससे हिंदी की प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भूमिका को मजबूत किया जा सके। ■



भारत सेमीकंडक्टर्स के लिए वैश्विक केंद्र



सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता और निवेश के अवसर इसे एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ समझौते किए गए हैं और भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिका के साथ भी अपना सहयोग मजबूत कर रहा है।

ब्यूरो

आर्थिक रणनीति के तहत सरकार भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित कर रही है। यह वैश्विक मांग में वृद्धि और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता से प्रेरित है। तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बढ़ती निर्भरता के साथ, भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति के क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए तत्पर है।

इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया-2024 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग का वैश्विक

केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और राज्य सरकारें भी इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल के परिणामस्वरूप अब तक भारत में ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की बात हो चुकी है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो उद्योग के विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में भारत में सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए ₹76,000 करोड़ के बजट के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी।

बनने के लिए तैयार है: श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सुधारों में विश्वास रखती है और देश के विनिर्माण आधार को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी बाजार को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अब चिप्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि जब कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया की सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियां भी लड़खड़ा गई थीं, तब भारत के बैंक बिना किसी व्यवधान के कार्य करते रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई, रुपये कार्ड, डिजीलॉकर और डिजियात्रा अब भारतीय जनजीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डेटा केंद्रों की मांग लगातार बढ़ रही है और देश वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

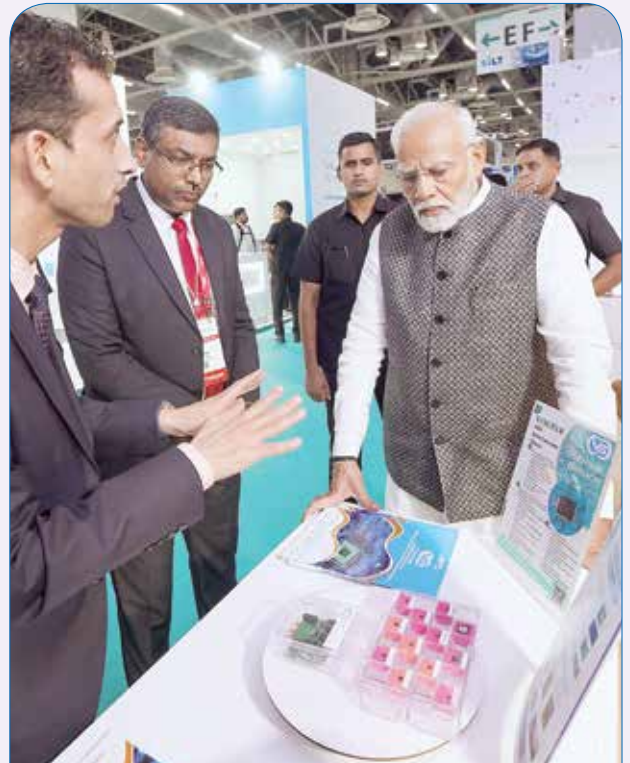
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजाइन के क्षेत्र में भारत दुनिया की प्रतिभा का 20% योगदान देता है और यह योगदान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया, 'भारत अपने छात्रों और पेशेवरों को उद्योग के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। देश 85,000 की एक सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहा है, जिसमें तकनीशियन, इंजीनियर और अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञ शामिल होंगे।'

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आवश्यक खनिजों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से कस्टम ड्यूटी में छूट लागू कर रहा है और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन नीलामियां आयोजित कर रहा है।

आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि भारत सभी क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है, हरित परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग का सामना कर रहा है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम, केरल में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) में एक सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के साथ साझेदारी में होगा। यह केंद्र वर्तमान और अगली पीढ़ी की चिप्स विकसित करने पर केंद्रित होगा।

प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया मिशन की हालिया उपलब्धियों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि यह मिशन पारदर्शी और कुशल शासन स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए, श्री मोदी ने बताया कि देशभर में मोबाइल हैंडसेट और डेटा की लागत को कम करने के लिए आवश्यक सुधार लागू किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि एक दशक पहले भारत मोबाइल फोन का सबसे बड़ा आयातक था, लेकिन अब यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक और निर्यातक बन चुका है।

प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया अब 'सिलिकॉन कूटनीति' के युग में प्रवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत को इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सप्लाई चेन काउंसिल



भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रगति के साथ क्रांति के कगार पर है, और उद्योगों को बदलने के लिए तैयार है। आज का भारत दुनिया में विश्वास पैदा कर रहा है और जब भी कोई चुनौती आती है, तो भारत पर भरोसा किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव का एक प्रमुख भागीदार है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ समझौते किए गए हैं और भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिका के साथ भी अपना सहयोग मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जबकि उद्योग निवेश और मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, केंद्र सरकार का दायित्व स्थिर नीतियों की स्थापना करना है, जो व्यवसायों के सुचारु संचालन में सहायक हों। ■

नए भारत की नई कूटनीति दिखी सिंगापुर और ब्रुनेई में



प्रधानमंत्री ने 3 सितंबर, 2024 को ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्राएं भारत की कूटनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस दौरान उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारियों को मजबूत किया। इन यात्राओं ने भारत की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति को क्षेत्र में उजागर किया, जिससे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को और प्रोत्साहन मिला और क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक प्रगति में योगदान हुआ।

पहली बार प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा की। ब्रुनेई के प्रमुख सुलतान हाजी हसनल बोलकिआह ने प्रधानमंत्री, श्री मोदी को आमंत्रित किया था। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है, जो दोनों देशों

मेरा सिंगापुर का दौरा बहुत ही फलदायी रहा है। यह निश्चित रूप से द्विपक्षीय संबंधों को और प्रोत्साहित करेगा और हमारे दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाएगा। मैं सिंगापुर की सरकार और उसके लोगों को उनके गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

के बीच संबंधों की गहराई को दिखाती है।

4 सितंबर को प्रधानमंत्री, श्री मोदी को ब्रुनेई की राजधानी बांडर सेरी

बेगवान में सुलतान बोलकिआह द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने फिनटेक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया। साथ ही क्षेत्रीय ढांचों जैसे कि एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) और इंडो-पैसिफिक के भीतर साझेदारियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ मेल खाता है।

प्रधानमंत्री, श्री मोदी 4-5 सितंबर को सिंगापुर की दो दिवसीय यात्रा के दौरान, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, श्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें रक्षा, डिजिटल तकनीक, हरी ऊर्जा और सेमीकंडक्टर शामिल हैं।

सिंगापुर के भारत में \$160 अरब के निवेश के प्रमुख भूमिका को देखते हुए, दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश के अवसरों को विस्तार देने का आह्वान किया। कनेक्टिविटी को मजबूत करने और ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि और सिंगापुर के निवेशकों के लिए इसके विशाल संभावनाओं को उजागर किया।

इन चर्चाओं ने अगस्त में आयोजित 2nd India Singapore Ministerial Roundtable के परिणामों पर आधारित होकर, उन्नत निर्माण, स्थिरता और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। यात्रा के दौरान, सेमीकंडक्टर, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी और दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर में थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की, जो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की। भारत की वृद्धि कथा में सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, उन्होंने सिंगापुर में 'इन्वेस्ट इंडिया' कार्यालय की स्थापना की घोषणा की, जो दोनों देशों के बीच निवेश और सहयोग को और सुविधाजनक बनाएगा।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति, श्री थार्मन शानमुगरत्नम से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति, श्री शानमुगरत्नम के भारत-सिंगापुर साझेदारी के प्रति उत्साही समर्थन की सराहना की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्राओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भों में भारत के रणनीतिक लक्ष्यों में भी योगदान दिया है। ये जुड़ाव



प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की।

दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत-सिंगापुर और भारत-ब्रुनेई साझेदारी आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में फलती-फूलती रहे। ■



भारतीय समुदायों ने ब्रुनेई में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

रेल संपर्क के विस्तार से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति



ब्यूरो

पू

वीं भारत में रेलवे बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 सितंबर को झारखंड के टाटानगर में ₹660 करोड़ से अधिक लागत वाली विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के तेज विकास के लिए आधुनिक रेलवे बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। इनमें प्रमुख पहलों के रूप में मधुपुर बाइपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो शामिल हैं, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे, बल्कि झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों के व्यवसायों, पेशेवरों, छात्रों और जनसंख्या को भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन से छह वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया। ये नई सेवाएं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बढ़ते बेड़े का हिस्सा हैं, जिन्हें क्षेत्र में प्रमुख मार्गों पर रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से पेश किया गया है। यह महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती हैं और सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की सार्वजनिक मांग अत्यधिक है और देश के हर राज्य में इन आधुनिक, उच्च गति की ट्रेनों को मेजबान बनाने की उत्सुकता है। उन्होंने दोहराया कि पूर्वी भारत में रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, जिससे व्यापार के अवसरों में वृद्धि होगी। पेशेवरों एवं छात्रों के लिए अधिक संभावनाएं बढ़ेंगी।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष रूप से वाराणसी-देवघर वंदे भारत ट्रेन के सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों पर प्रकाश डाला, जो बाबा बैद्यनाथ

पूर्वी भारत में रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। वंदे भारत ट्रेनें व्यापारियों और छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाएंगी और आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी तेजी प्रदान करेंगी।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए रास्ते खोलेगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन झारखंड में पर्यटन और औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय जनसंख्या के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

रेल परिवहन के अलावा, प्रधानमंत्री ने आवास विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के 32,000 लाभार्थियों को पत्र वितरित किए। उन्होंने इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की पहली किस्त भी जारी की, जो ग्रामीण परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

झारखंड के राज्यपाल, श्री संतोष गंगवार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

35 वर्षों से चल रहा संघर्ष हुआ समाप्त शांतिपूर्ण, समृद्ध व उग्रवाद-मुक्त पूर्वोत्तर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

केंद्र सरकार पर विश्वास जताते हुए नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने त्रिपुरा में पिछले 35 वर्षों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। दोनों उग्रवादी समूहों ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की पहल पर भरोसा जताते हुए शांति प्रक्रिया में शामिल होने की घोषणा की।



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. माणिक साहा, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन।

ब्यूरो

कें द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह का कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हर शांति समझौते को दिल से और 'लेटर एंड स्पिरिट' में लागू करके दिखाया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बू-रियांग समझौता होने के बाद आज हजारों बू-रियांग भाई अपने घरों में शांति से रह रहे हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके रोजगार की चिंता की जा रही है। सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है।

04 सितंबर को नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान श्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि त्रिपुरा के साथ हुए समझौते का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि गृह मंत्रालय इस समझौते को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उनका कहना था कि हम सभी मिलकर एक सशक्त और समृद्ध त्रिपुरा के निर्माण की दिशा में काम करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में त्रिपुरा से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा लिया था, जो एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने नॉर्थईस्ट के अधिकांश हिस्सों से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाकर क्षेत्र को सशस्त्र बलों की उपस्थिति से मुक्त किया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के शांतिपूर्ण, समृद्ध और उग्रवाद-मुक्त नॉर्थ ईस्ट के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य त्रिपुरा में उग्रवाद की समस्याओं को समाप्त करना और क्षेत्र में स्थायी शांति एवं विकास को बढ़ावा देना है। NLFT और ATTF जैसे उग्रवादी समूहों का इस शांति प्रक्रिया में शामिल होना सरकार की सशक्त और समर्पित रणनीति का परिणाम है, जो नॉर्थ ईस्ट के विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देती है। चार सितंबर को नई दिल्ली में हुए समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का ये समझौता नॉर्थ ईस्ट के लिए 12वां और त्रिपुरा से जुड़ा तीसरा समझौता है। इन 12 समझौतों के जरिए दोनों तरफ से हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने की बड़ी पहल की गई है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज के समझौते के तहत 328 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर न सिर्फ विकसित त्रिपुरा, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए ₹250 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। ■

साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत स्तंभ बना 'I4C'

I4C के तहत दिल्ली में एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। अब तक 1100 से अधिक अधिकारियों को साइबर फॉरेंसिक में प्रशिक्षित किया गया है और इस अभियान को जिलों और तहसील तक ले जाने का बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 10 सितंबर, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

ब्यूरो

भा

रातीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृह मंत्री ने 'I4C' को देश की साइबर सुरक्षा का एक मजबूत स्तम्भ बताते हुए इसके महत्व को उजागर किया है। 'I4C' का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, उनकी निगरानी और अपराधियों की पहचान करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना है। यह केंद्र विभिन्न साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में राज्य और केंद्र सरकारों के प्रयासों को एकत्रित करता है और साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीतियों पर काम करता है।

10 सितंबर को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए

कोई एक संस्था या इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित नहीं कर सकते इसके लिए इसके सभी स्टैक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर आकर साथ में काम करना होगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) राष्ट्र को समर्पित किया और समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली) का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने 'Cyber Commandos' कार्यक्रम और संदिग्ध रजिस्ट्री (Suspect Registry) का भी उद्घाटन किया। साथ ही गृह मंत्री ने I4C के नए लोगो,

प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने भी अभियान की सराहना की



साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 'I4C' देश में साइबर अपराध के नियंत्रण की दिशा में प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है। श्री अमिताभ बच्चन ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री बच्चन ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के आग्रह पर वे इस अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर देश को इस समस्या से मुक्त कराएं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय देश में एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं श्री अमिताभ बच्चन जी को इस अभियान से जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। उनकी सक्रिय भागीदारी साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के हमारे मिशन को और गति देगी।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

विजन और मिशन का भी लोकार्पण किया।

I4C का उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित साइबरस्पेस बनाना है। इसके तहत एक प्रभावी ढांचा और तंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो साइबर अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और अभियोजन के लिए समर्पित है। यह पहल देश भर में उभरते डिजिटल खतरों का मजबूत और समन्वित तरीके से मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री अमित शाह ने कहा साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना थी, जिसका शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ साइबर कमांडो, समन्वय प्लेटफॉर्म और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का भी शुभारंभ हुआ है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में हर राज्य के पास साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री अलग-अलग रहने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्यों की अपनी सीमा है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए और राज्यों को इसके साथ जोड़कर साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाए। इस पहल से आने वाले दिनों में साइबर अपराधों की रोकथाम में हमें बहुत मदद मिलेगी।

श्री अमित शाह ने बताया कि सीएफएमसी के माध्यम से बैंक, वित्तीय संस्थान, टेलीकॉम कंपनियां, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और पुलिस को एक ही मंच पर लाकर इस केंद्र का गठन किया गया है, जो आने वाले दिनों में साइबर अपराध की रोकथाम का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बनेगा। इस पहल के हिस्से के रूप में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के आधार पर विभिन्न पहचानकताओं की एक संदिग्ध रजिस्ट्री बनाई जा रही है।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, निदेशक आसूचना ब्यूरो, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अनेक सरकारी संगठनों के अधिकारी, विभिन्न बैंकों/वित्तीय मध्यस्थों, फिनटेक, मीडिया, साइबर कमांडो, NCC और NSS के डेटे शामिल थे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 को 25 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2024 को 95 करोड़ है। उन्होंने कहा कि डाउनलोड स्पीड बढ़ने और लागत कम होने से डेटा की खपत में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले औसत उपयोग 0.26 GB था, जो लगभग 78 गुना बढ़ोतरी के साथ आज 20.27GB हो गया है। श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया के इनीशिएटिव के कारण देश में कई सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं।

विश्व का 46% डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि जब डिजिटल अकाउंट और डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, तो डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षा की जरूरत भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में देश की मात्र 600 पंचायत इंटरनेट से जुड़ी थीं, आज 2,13,000 पंचायत जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन और डिजिटल डेटा का उपयोग बढ़ने से इसे साइबर फ्रॉड से सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी बहुत अधिक बढ़ गई है। ■

राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों के समग्र समाधान का रोडमैप तैयार



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2024 में हुए शामिल।

ब्यूरो

भा रत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थिति जटिल है, जो सीमा पार आतंकवाद, साइबर हमले और संगठित अपराध जैसे अनेक नए और जटिल खतरों से घिरी है। इन चुनौतियों के महत्व को देखते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 13 सितंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2024 का उद्घाटन किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने आतंकवाद-रोधी प्रयासों को सशक्त करने के लिए एक विस्तृत रणनीति का प्रस्ताव रखा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने आतंकवाद-रोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आतंकवाद-रोधी दस्तों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री शाह ने पुलिस महानिदेशकों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों जैसे वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को संबोधित करने में हुए महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। साथ ही, उन्होंने उभरते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान और समाधान पर भी बल दिया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के संदर्भ में पुलिस महानिदेशकों से आग्रह किया

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना था, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों की भागीदारी से सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया गया।

कि वे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें और पीड़ितों को न्याय त्वरित और कुशलता से दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने सभी पुलिस महानिदेशकों से आंतरिक सुरक्षा ढांचे को बहुआयामी दृष्टिकोण, डेटा विश्लेषण और नई तकनीकों को अपनाकर मजबूत करने की अपील की। इसके साथ ही, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बनाए गए डेटाबेस का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

सम्मेलन में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न प्रतिभागियों के सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान किया गया।

इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय एवं श्री बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, अपर/उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। ■

नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए उन्नत तकनीक का लिया जा रहा सहारा

सीमा सुरक्षा बल उन्नत तकनीक, चौबीसों घंटे गश्त और मजबूत अंतर-एजेंसी सहयोग के साथ निरंतर निगरानी के माध्यम से भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रग तस्करी द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल को सफलतापूर्वक रोक रहा है।

ब्यूरो

सी

सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करता है, सीमा पार से घुसपैठ और ड्रग तस्करी जैसे कई खतरों का सामना करता है। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सीमा सुरक्षा बल बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखता है।

सीमा सुरक्षा बल उन्नत तकनीक, चौबीसों घंटे गश्त और मजबूत अंतर-एजेंसी सहयोग के साथ निरंतर निगरानी के माध्यम से ड्रग तस्करी सिंडिकेट द्वारा ड्रोन के उपयोग का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है।

ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल सीमा सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसे-जैसे ड्रोन तकनीक अधिक सुलभ होती जा रही है, तस्कर ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध सामग्री के परिवहन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तस्करी का यह तरीका न केवल पारंपरिक सीमा सुरक्षा उपायों को जटिल बनाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए जोखिम भी पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के प्रयासों के कारण ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से नाकाम किया जा रहा है।

हाल के दिनों में ड्रग तस्करी को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसकी मुख्य वजह रही सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता। 15 सितंबर को पंजाब के तरनतारन जिले में रात को गश्त के दौरान सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों ने नौशेरा ढल्ला गांव के पास 1.146 किलोग्राम हेरोइन से भरे दो पैकेट जब्त किए। ड्रोन के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत सीमा सुरक्षा बल ने 12 सितंबर को तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे एक ड्रोन को निष्क्रिय किया। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस कर्मियों के साथ एक संयुक्त तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप गिलपान गांव के पास एक असेंबल क्वाडकोप्टर और 6.230 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई।

एक अन्य घटना में सीमा सुरक्षा बल कर्मियों ने 2 सितंबर को पंजाब



पंजाब के तरनतारन जिले के नौशेरा ढल्ला के पास सीमा सुरक्षा बल ने हेरोइन के साथ एक ड्रोन जब्त किया है।

के फाजिल्का जिले के चूड़ीवाला विशती गांव के पास सीमा पर घूमते हुए एक ड्रोन का पता लगाया। सीमा सुरक्षा बल ने ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया और लगभग 500 ग्राम वजन की हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया।

सीमा क्षेत्रों पर सतर्कता बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के कर्मी उन्नत निगरानी उपकरणों जैसे हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर्स (एचएचटीआई), नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी) और टिवन टेलीस्कोप मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निगरानी प्रयासों को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की टोही और अवलोकन प्रणाली (LORROS) और युद्धक्षेत्र निगरानी रडार (BFSR) भी तैनात किए गए हैं। ड्रग तस्करी द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ अंतराष्ट्रीय सीमा पर प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, इन्फ्रारेड सेंसर और अलार्म सहित एकीकृत निगरानी तकनीक तैनात की गई है। ■

पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता का नाम है 'एसवीपीएनपीए'

ब्यूरो

स रदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA), हैदराबाद ने 15 सितंबर को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भारतीय पुलिस सेवा के भविष्य के नेताओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम में निदेशक की परेड के साथ-साथ एक जीवंत सांस्कृतिक संध्या भी शामिल थी, जिसमें प्रशिक्षु अधिकारियों की अद्भुत प्रतिभाओं को दर्शाया गया।

अकादमी के निदेशक, श्री अमित गर्ग ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी और प्रोत्साहन प्रदान किया। उनका संबोधन प्रेरणा से भरा था, जिसमें उन्होंने प्रोबेशनरों को न्याय और अखंडता बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का याद दिलाया। प्रतिष्ठित निदेशक की प्रशंसा सूची और पदक 35 अधिकारियों को उनके अथक प्रयासों और अकादमी के मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किए गए।

15 सितंबर, 1948 को राजस्थान के माउंट आबू में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में स्थापित, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने महत्वपूर्ण विकास किया है। स्वतंत्रता से पहले, भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए प्रोबेशनरी प्रशिक्षण विभिन्न प्रांतीय महाविद्यालयों में बिना किसी मानकीकृत प्रणाली के आयोजित किया जाता था। पहले गृह मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल ने IPS के गठन का समर्थन किया, यह मानते हुए कि एक मजबूत अखिल भारतीय सेवा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। इस दृष्टिकोण ने एक सामान्य प्रशिक्षण ढांचे की स्थापना की नींव रखी।

यह अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के अलावा, यह एसपी, डीआईजी और आईजी/अतिरिक्त डीजी स्तर के अधिकारियों के लिए अनिवार्य मध्य-कार्यकाल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। साथ ही, देश के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए भारतीय पुलिस सेवा इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स, और सभी स्तरों के पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष विषयों पर संक्षिप्त कोर्स, संगोष्ठियां, और कार्यशालाएं आयोजित करती है। विदेशी पुलिस अधिकारी और सेना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्व सेवा, न्यायपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियों आदि से जुड़े अधिकारी भी समय-समय पर यहां आयोजित विशेष कोर्स में शामिल होते हैं। अकादमी पुलिस विषयों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने



हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए)।

पिछले सात दशकों में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने एक शानदार विरासत बनाई है, जिसमें हजारों युवा पुरुषों और महिलाओं को पेशेवर और साहसी पुलिस अधिकारियों में ढाला गया है। अकादमी के समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद, हमारे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा उच्च दक्षता वाले पुलिस बलों के सुरक्षित हाथों में है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

वर्ष 1967 में, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रखा गया। वर्ष 1974 में, इसे सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित किया गया, जो IPS के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। वर्ष 1971 में डॉ. एमएस गोरे की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने अकादमी को एक स्थाई स्थान पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की। फरवरी 1975 में, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थापित किया गया, जो इसके विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ■

सरोकार, सरकार और समाज



केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने पटना में हिंदी पखवाड़ा में हिस्सा लिया।

ब्यूरो

कें द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने 8 सितंबर को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित हिंदी पखवाड़ा और पुस्तक चौदस मेला के आठवें दिन 'कवयित्री-सम्मेलन' का उद्घाटन करते हुए हिंदी भाषा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश को एक सूत्र में जोड़ने और परस्पर सौहार्द बढ़ाने के लिए एक संपर्क-भाषा का होना आवश्यक है और इस दिशा में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री नित्यानंद राय ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयासों की सराहना की, विशेष रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए उनके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के समय हिंदी को बढ़ावा देने वाले प्रतिनिधि नहीं थे, अन्यथा आज हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होती।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार ने गैर-हिंदी भाषी प्रदेशों के अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की है और हमारी सरकार हिंदी को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास करेगी। इस अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने श्री नित्यानंद राय का अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मेलन की शीर्ष समिति 'स्थायी समिति' की मानद सदस्यता प्रदान की।

● 5 सितंबर को पटना के ए.एन. कॉलेज में विद्यार्थी विकास परिषद द्वारा

आयोजित प्रो. रविंद्र केसरी शिक्षक सम्मान समारोह में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय शामिल हुए। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना हमारे समाज की एक अनमोल परंपरा है, जो हमें ज्ञान के पथ पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

● तेलंगाना में आपदा के समय बेहतर बचाव और पुनर्वास आदि की सुविधा के लिए केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री, श्री बंडी संजय कुमार ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह से बात की। तेलंगाना में NDRF फंड्स की स्वीकृति और उपयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई। श्री अमित शाह ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उनके निर्देशानुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आपदा प्रभाग के निदेशक ने आदेश जारी किए।

श्री बंडी संजय कुमार के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय टीम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेगी। लेखाकार महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार के पास एसडीआरएफ फंड में ₹1345 करोड़ उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार राष्ट्रीय आपदा निधि का अपना हिस्सा जारी कर रही है। तेलंगाना सरकार को सलाह दी गई है कि वह राज्य के एसडीआरएफ फंड्स का उपयोग करे। ■

राष्ट्र की एकता और विकास के लिए महत्वपूर्ण हिंदी

वर्तमान केंद्र सरकार ने हिंदी के प्रचार-प्रसार और इसके विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य हिंदी को न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं। नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के अंतर्गत

मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया गया है, जिसमें हिंदी का भी प्रमुख स्थान है। इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देकर उन्हें अधिक सक्षम बनाना है।

सरकार ने हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और सम्मेलनों का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में भाषण देकर इसका प्रचार किया है, जिससे हिंदी की पहुंच विश्वभर में बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी हिंदी के प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की प्राथमिकता रही है कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग हो। गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने हिंदी को राष्ट्र की एकता और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए इसके प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। उनका मानना है कि हिंदी न केवल संचार का एक साधन है, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान और एकता का भी प्रतीक है। उनका मानना है कि हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर सकती है और इसके प्रयोग से देश में संचार और प्रशासन अधिक प्रभावी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में भाषण देकर इसे प्रोत्साहित किया है। इससे हिंदी भाषी लोगों को वैश्विक स्तर पर जुड़ने और अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिला है।

श्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग करें और लोगों से संवाद के लिए हिंदी का



डॉ. सुमीत जेथी

सहारा लें। इसके अंतर्गत, सरकारी दस्तावेज, संचार सामग्री, और वेबसाइट्स हिंदी में उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत, सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स और पोर्टल्स को हिंदी में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम जनता इन सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सके। सरकारी मोबाइल ऐप्स, ई-गवर्नेंस सेवाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में हिंदी का विकल्प

उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोग अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दौरान, हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाता है।

श्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर कई बार इस बात पर जोर दिया है कि सभी भारतीयों को हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाना चाहिए, ताकि देश की एकता और अखंडता मजबूत हो सके। उनके भाषणों और अपीलों में हिंदी को राष्ट्र की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता और प्रेम बढ़ा है। वे हिंदी को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं मिलकर देश की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध कर सकती हैं। उन्होंने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है ताकि देश के विभिन्न राज्यों और भाषाई समुदायों के बीच समन्वय और एकता स्थापित हो सके।

सरकार का प्रयास है कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि यह पूरे देश में एकता और समन्वय स्थापित करने का माध्यम बन सके। इसके साथ ही, हिंदी का प्रयोग करते हुए अन्य भाषाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की नीति को भी अपनाया गया है। इन प्रयासों से स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता है कि हिंदी को न केवल सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्थापित किया जाए, बल्कि इसे आम जनमानस की भाषा के रूप में भी लोकप्रिय बनाया जाए।

(पूर्व सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)



लेह-लद्दाख के चोगलमसर स्थित आईटीबीपी के 16वीं बटालियन में 'एक पेड़ मां के नाम' नामक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान हिमवीर ने लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए हरियाली भरे भविष्य का संकल्प लिया।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सीआरपीएफ कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी के तहत, ध्यान और वेलनेस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस समझौता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'वॉयस दैट केयर्स' है, जो एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, जहां छह क्षेत्रीय भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।



एनएसजी ने मानवाधिकार आयोग की ओर से मानेसर में इंटर-CAPFs वाद-विवाद प्रतियोगिता 2024 (दिल्ली जोन) का आयोजन किया। हिंदी श्रेणी में असम राइफल्स और एनएसजी को क्रमशः विजेता और उपविजेता घोषित किया गया, जबकि अंग्रेजी श्रेणी में सीआईएसएफ और असम राइफल्स ने विजेता और उपविजेता का स्थान प्राप्त किया।



भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

<https://bharatkeveer.gov.in>

दिशा-निर्देश

- ⇒ आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- ⇒ अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- ⇒ भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

नोट: लेख की जानकारी विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों और सरकारी आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित



हिंदी ने विश्वभर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037